

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-826
उत्तर दिनांक 04/02/2026 को दिया गया

परमाणु ऊर्जा विभाग की विस्तार परियोजनाएं

826. श्री परषोत्तमभाई रुपाला

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

- (क) परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) की अधीनस्थ इकाइयों, बोर्डों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित इसकी सभी प्रस्तावित और चल रही विस्तार परियोजनाओं की अनुमोदित लागत और क्षमता संबंधी लक्ष्यों सहित परियोजनावार ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए समय-सीमा की समीक्षा की है तथा समय और लागत में वृद्धि को रोकने के लिए उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या डीएई ने वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं का आकलन किया है और लक्षित तरीके से भर्ती शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या सरकार का इन रणनीतिक पहलों के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने और समय पर पूरा करने के लिए डीएई के सेवानिवृत्त वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों की विशेषज्ञता का उपयोग करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

- (क) (ए) वर्तमान में, 13100 मेगावाट की कुल क्षमता के 17 नाभिकीय विद्युत रिएक्टर कार्यान्वयनाधीन हैं, जिनमें सात नाभिकीय रिएक्टर निर्माणाधीन और दस रिएक्टर पूर्व-परियोजना गतिविधियों के अधीन हैं। विवरण निम्नानुसार है:

स्थल	परियोजना	क्षमता (मेगावाट)	भौतिक प्रगति	अनुमोदित लागत (रूपए करोड़ में)	पूर्ण होने का अनुमानित वर्ष
निर्माण/कमीशनन के अधीन परियोजनाएं					
राजस्थान	आरएपीपी-7 ^s व 8	2 X 700	98.60	22,924	2026
कुडनकुलम, तमिलनाडु	केकेएनपीपी -3 व 4	2 X 1000	80.51	68,893	2027
	केकेएनपीपी-5 व 6	2 X 1000	41.56	68,893	2030
गोरखपुर, हरियाणा	जीएचएवीपी-1 व 2	2 X 700	निर्माण कार्य प्रगति पर है।	20,594	2032

पूर्व-परियोजना गतिविधियों के अधीन परियोजनाएं					
कैगा, कर्नाटक	कैगा-5 व 6	2 X 700	विभिन्न स्तरों पर पूर्व- परियोजना गतिविधियों के अधीन	1,05,000	वर्ष 2031-32 तक क्रमिक रूप से
गोरखपुर, हरियाणा	जीएचएवीपी - 3 व 4	2 X 700			
चुटका, मध्य प्रदेश	चुटका -1 व 2	2 X 700			
माही बांसवाड़ा, राजस्थान	माही बांसवाड़ा -1 व 2*	2 X 700			
	माही बांसवाड़ा -3 व 4*	2 X 700			

§ आरएपीपी-7 व 8 की यूनिट 7 (700 मेगावाट) ने दिनांक 15.04.2025 को वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ किया।

* माही बांसवाड़ा-1 व 2 और माही बांसवाड़ा-3 व 4 का कार्यान्वयन एनपीसीआईएल और एनटीपीसी के संयुक्त उद्यम, अश्विनी द्वारा किया जा रहा है।

(बी) भाविनि वर्तमान में कल्पाक्कम, तमिलनाडु में 500 मेगावाट प्रोटोटाइप द्रुत प्रजनक रिएक्टर (पीएफबीआर) परियोजना के कमीशनन का कार्य कर रही है। सरकार ने कल्पाक्कम, तमिलनाडु में एफबीआर 1 व 2 परियोजना की 2 X 500 मेगावाट की द्वि-यूनिटों के लिए पूर्व-परियोजना गतिविधियां संचालित करने हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया है। पीएफबीआर के प्रथम क्रांतिकता प्राप्त होने के उपरांत, एफबीआर 1 व 2 परियोजनाओं की वित्तीय मंजूरी के लिए सरकार से संपर्क किया जाएगा।

(ख) (ए) हां। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) और परमाणु ऊर्जा विभाग (डीईई) द्वारा भी कई स्तरों पर समय-समय पर परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाती है। परियोजना गतिविधियों की प्रगति की कई स्तरों पर सतत निगरानी, अवरोधों की समय पर पहचान और आवश्यक मध्यवर्ती सुधार करने, विक्रेताओं/ठेकेदारों के साथ नियमित बैठकें और निर्माण गतिविधियों को यथासंभव पुनः अनुक्रमित करने से संबंधित कार्य, परियोजनाओं का कार्यान्वयन समय पर सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है।

(बी) भाविनि के पास परियोजना प्रगति की निगरानी के लिए निम्नलिखित संस्थागत व्यवस्था उपलब्ध है; कमीशनन संबंधी प्रगति की समीक्षा और बेहतर संसाधन पूलिंग हेतु डिजाइनरों के साथ इकाई स्तर पर साप्ताहिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। परियोजना की समीक्षा भाविनि बोर्ड द्वारा त्रैमासिक आधार पर भी की जाती है। ये समीक्षाएं संसाधनों के पुनःआवंटन, त्वरित निर्णय लेने और परियोजना में तेजी लाने में सहायक होती हैं।

(ग) हां। एनपीसीआईएल ने विस्तार कार्यक्रम की आवश्यकताओं और भर्ती, प्रशिक्षण तथा लाइसेंसिंग में निहित समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्तरों पर कर्मियों की संकेन्द्रित भर्ती आरम्भ की है।

ईसीआईएल में 80 स्नातक अभियंता प्रशिक्षुओं को शामिल करने के लिए भर्ती प्रक्रिया आरंभ की गई है।

(घ)

परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्तर की "डीईई-राजा रामन्ना चेर" (डीईई-आरआरसी) योजना आरम्भ की गई है, जिसका उद्देश्य उन सेवानिवृत्त सक्रिय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और प्रौद्योगिकीविदों की सेवाओं का उपयोग करना है, जो डीईई की इकाइयों या किसी राष्ट्रीय प्रयोगशाला या विश्वविद्यालय या संस्थान में अपने विशिष्ट विषयों में उच्च स्तरीय अनुसंधान में शामिल रहे हैं और सेवानिवृत्ति के बाद डीईई द्वारा निर्धारित विषयों पर अनुसंधान एवं विकास और अध्ययन करने के इच्छुक हैं।

विभाग द्वारा "डीईई-होमी सेठना चेर" (डीईई-एचएससी) योजना भी आरम्भ की गई है, जिसका उद्देश्य उन सेवानिवृत्त सक्रिय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और प्रौद्योगिकीविदों की सेवाओं का उपयोग करना है, जो डीईई की इकाइयों में अपने विशिष्ट विषयों में उच्च स्तरीय अनुसंधान में शामिल रहे हैं और सेवानिवृत्ति के बाद डीईई द्वारा निर्धारित विषयों पर अनुसंधान एवं विकास, नीति और योजना अध्ययन करने के इच्छुक हैं।

इन योजनाओं का उद्देश्य उन सेवानिवृत्त सक्रिय वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और प्रौद्योगिकीविदों की सेवाओं का लाभ उठाना है जिन्होंने महत्वपूर्ण और संवेदनशील प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में कार्य किया है और जो विभाग द्वारा निर्धारित विषयों के अनुसार डीईई की अनुसंधान परियोजनाओं, नीति और योजना गतिविधियों में नियमित रूप से रचनात्मक योगदान दे सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, डीईई-आरआरसी अध्येतावृत्ति प्राप्तकर्ता परमाणु ऊर्जा से संबंधित विषयों पर मोनोग्राफ या पुस्तकें लिख सकते हैं और डीईई-एचएससी पुरस्कार प्राप्तकर्ता महत्वपूर्ण विषयों या परियोजनाओं पर कार्य करेंगे और विभाग को निर्धारित समयावधि के भीतर एक विस्तृत विश्लेषण प्रदान करने के उद्देश्य से नीतिगत मुद्दों पर अध्ययन करेंगे।
